



राज्यपाल का पद और संबंधित चित्ताएँ

प्रलिस के लयि:

राज्यपाल के पद से संबंधित प्रावधान और शक्तियाँ, सरकारिया आयोग (1988), वेंकटचलैया आयोग (2002), पुंछी आयोग (2010), बीपी सघिल बनाम भारत संघ

मेन्स के लयि:

राज्यपालों के पद से संबंधित चित्ताएँ, वभिनिन समतियाँ की सफारिशें एवं आगे की राह

स्रोत: द हट्टि

चरचा में क्योँ?

हाल ही में [राष्ट्रपति](#) ने पूरव केंद्रीय गृह सचवि अजय भल्ला को मणपुरि का [राज्यपाल](#), जनरल वी.के. सहि (सेवानवृत्त) को मजोरम का राज्यपाल तथा केरल के राज्यपाल आरफि मोहम्मद खान को पुनः बहिर का राज्यपाल नयुक्त कयि।

राज्यपाल के पद से संबंधित क्या प्रावधान हैं?

- संवधानिक प्रावधान: भारतीय संवधान के अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लयि एक राज्यपाल की नयुक्ति का प्रावधान है, जसिमें एक ही वयक्त को कई राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है।
 - यह राज्य का संवधानिक प्रमुख होता है तथा [मंत्रपरिषद](#) की सलाह पर कार्य करता है।
- भारतीय संवधान के अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल को प्रदान की गई है।
 - राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में नहिती होती है और संवधान के प्रावधानों के अनुसार, वह इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से या अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से कर सकता है।
- राज्यपाल की नयुक्ति: अनुच्छेद 155 के अनुसार कसिी राज्य के राज्यपाल की नयुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- यद्यपि राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नयुक्त एवं पुनर्नयुक्त कयि जाता है फरि भी उसे भारत सरकार का प्राधिकारी नहीं माना जाता है।
 - राज्यपाल को अपने कार्यकाल के दौरान कसिी भी लाभ के पद पर नहीं रहना चाहयि।
- राज्यपाल के पद हेतु अरहताएँ: वयक्त को भारत का नागरिक होना चाहयि, कम से कम 35 वर्ष का होना चाहयि तथा संसद या कसिी राज्य वधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहयि।
- शपथ:
 - अनुच्छेद 159 के तहत, [राज्यपाल](#) को पद ग्रहण करने से पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम उपलब्ध न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेनी होती है।
- वधानमंडल की शक्तियाँ:
 - अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल वधानसभा को भंग करने की सफारिश (यदि कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती है या [मुख्यमंत्री](#) की सलाह पर) कर सकते हैं लेकिन यह शक्ति विशिष्ट शर्तों के अधीन होने के साथ पूरी तरह से वविकाधीन नहीं है।
 - अनुच्छेद 175(2) के तहत राज्यपाल सरकार के बहुमत को सत्यापति करने के लयि फ्लोर टेस्ट करवा सकते हैं एवं वधियकों या अन्य मामलों पर वचिर करने हेतु वधियिका को संदेश भेज सकते हैं।
 - अनुच्छेद 176 के तहत, राज्यपाल आम चुनावों के बाद पहले सत्र में तथा प्रतविरष वधानमंडल को संबोधित करते हुए वधानसभा या दोनों सदनों को बुलाने के कारण बताते हैं।
 - राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल भी [धन वधियक](#) पर मंजूरी में वलिंब कर सकते हैं और सफारिशें कर सकते हैं, लेकिन वधियिका उन्हें स्वीकार करने के लयि बाध्य नहीं है।
- संवधानिक वविकाधीन शक्तियाँ:
 - मुख्यमंत्री की नयुक्ति तब की जाती है जब राज्य वधानसभा में कसिी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न हो या जब पदस्थ मुख्यमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो।

- मंत्रपरिषद को बरखास्त करना जब वह राज्य विधानमंडल का विश्वास सदिध न कर सके।
- यदि मंत्रपरिषद अपना बहुमत खो दे तो राज्य विधान सभा को भंग किया जा सकता है।
- राज्यपाल का कार्यकाल:
 - अनुच्छेद 156 में प्रावधान है कि राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर ही पद धारण करता है, जिसका सामान्य कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष का होता है।
 - राज्यपाल को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा बरखास्त किया जा सकता है।
 - राज्यपाल तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि उनका उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता, यहाँ तक कि उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी।

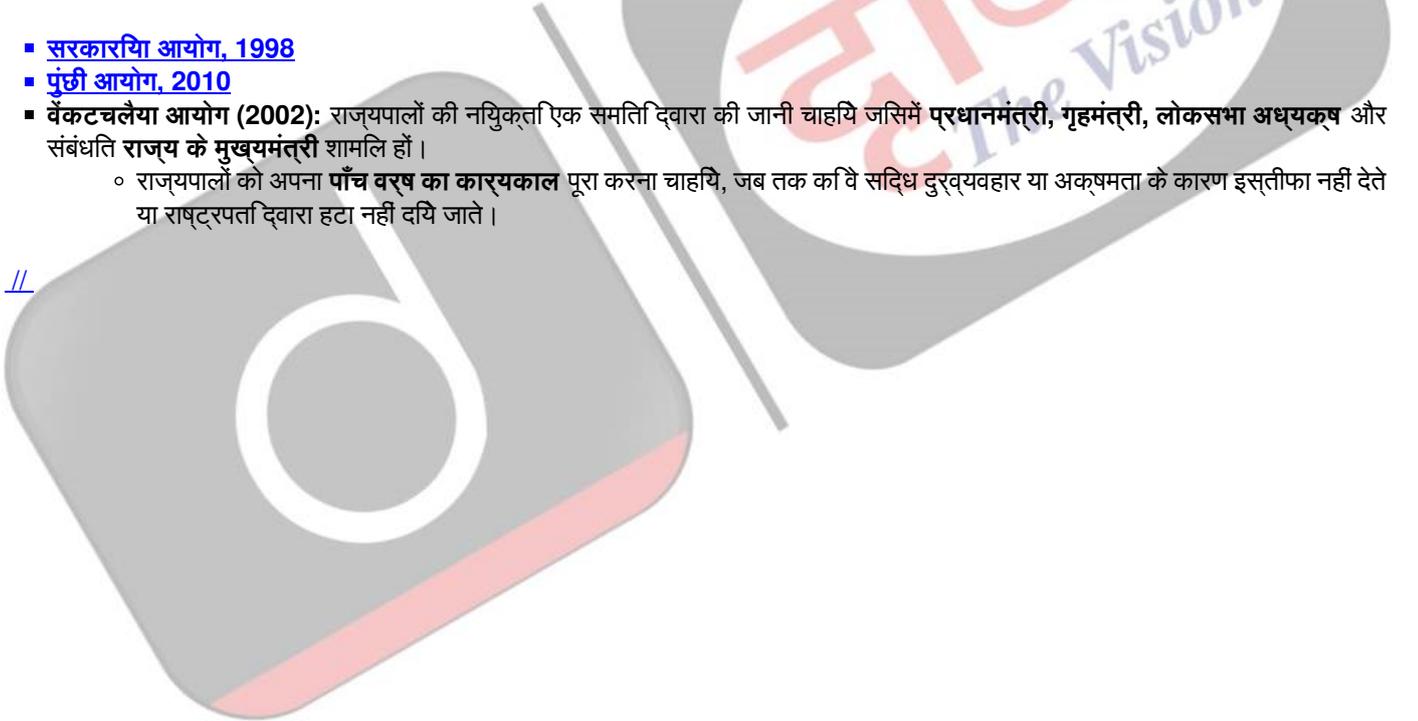
राज्यपाल के पद से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

- राजनीतिक तटस्थता और नष्पक्षता: केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपालों को प्रायः सत्तारूढ़ पार्टी के साथ राजनीतिक संबंधों के लिये आलोचना का सामना करना पड़ता है, जिससे नष्पक्षता और केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करने को लेकर चर्चा पैदा होती है।
- अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग: अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सफ़ारिश करने की राज्यपाल की शक्ति प्रायः संवैधानिक लोकाचार और संघवाद के संबंध में बहस का विषय बनती है।
- विधायकों पर विलंबित स्वीकृति: राज्यपाल कभी-कभी राज्य विधायकों पर मंजूरी देने में देरी करते हैं या रोक लेते हैं, जिससे कानून पारित होने में बाधा उत्पन्न होती है। इससे उनकी जवाबदेही और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के पालन को लेकर चर्चा पैदा होती है, जिससे शासन में अनिश्चिता पैदा होती है।
 - वर्ष 2023 में, तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि को राज्य विधायकों पर मंजूरी में देरी करके कथित रूप से "पॉकेट वीटो" का उपयोग करने के लिये आलोचना का सामना करना पड़ा।
- राज्य प्रशासन में हस्तक्षेप: राज्य प्रशासन में राज्यपालों का हस्तक्षेप, जैसे कि स्वयं को सक्रिय राजनीति में शामिल करना, प्रायः नस्वाचित अधिकारियों और लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के साथ टकराव पैदा करता है।

राज्यपाल से संबंधित समितियाँ

- सरकारिया आयोग, 1998
- पुंछी आयोग, 2010
- वेकटचलैया आयोग (2002): राज्यपालों की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जानी चाहिये जिसमें प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हों।
 - राज्यपालों को अपना पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा करना चाहिये, जब तक कि वे सिद्धि दुर्व्यवहार या अक्षमता के कारण इस्तीफा नहीं देते या राष्ट्रपति द्वारा हटा नहीं दिये जाते।

//





राज्यपाल

(भाग-III)

राष्ट्रपति- अनुच्छेद 52-78 (भाग V); राज्यपाल- अनुच्छेद 153-167 (भाग VI)

राज्यपाल व राष्ट्रपति-समानताएँ

समानता का बिंदु	विशेषताएँ
प्रमुख	♦ दोनों अपने स्तर पर नाममात्र के कार्यकारी प्रमुख (संवैधानिक/शीर्षक प्रमुख) हैं
अध्यादेशों का प्रख्यापन	♦ दोनों के पास यह शक्ति है (अनुच्छेद 123- राष्ट्रपति; अनुच्छेद 213- राज्यपाल)
सिविल और आपराधिक कार्यवाही	♦ दोनों कार्यकाल के दौरान किसी भी आपराधिक कार्यवाही से मुक्त हैं; गिरफ्तार या कैद नहीं किया जा सकता। ♦ 2 महीने का नोटिस देकर सिविल कार्यवाही शुरू की जा सकती है।
पुनर्नियुक्ति/पुनर्निर्वाचन	♦ दोनों एक ही कार्यालय में पुनर्नियुक्ति/पुनर्निर्वाचन के पात्र हैं
नियुक्ति अधिकारी	♦ जिस प्रकार राष्ट्रपति राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्तियाँ करता है वैसे ही राज्यपाल राज्य स्तर पर नियुक्ति करता है (लोक सेवा आयोग के सदस्य, न्यायालयों के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त आदि)।
विधानमंडल में भूमिका	♦ राज्य/संघ विधानमंडल को आहूत करने या सत्रावसान करने और राज्य विधानसभा/लोकसभा को भंग करने की शक्ति
वित्तीय शक्तियाँ	♦ राज्य/संघ स्तर पर वित्त आयोग का गठन करना
परिस्थितिजन्य विवेकाधीन शक्ति	♦ प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री की नियुक्ति (प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री की मृत्यु के मामले में या जब किसी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है) ♦ मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी ♦ लोकसभा/राज्य विधायिका को भंग करना

राज्यपाल बनाम राष्ट्रपति

अंतर का बिंदु	राष्ट्रपति	राज्यपाल
निर्वाचन	अप्रत्यक्ष चुनाव	राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
प्रसादपर्यतता का सिद्धांत	प्रसादपर्यतता के सिद्धांत की कोई अवधारणा नहीं	राष्ट्रपति के प्रसादपर्यत पद पर बना रहता है
अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा	किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकता है	भूमिका सलाह/परामर्श के अधीन
संविधान में संशोधन	विधेयक पर इसकी सहमति आवश्यक है	संविधान संशोधन में कोई भूमिका नहीं
क्षमादान शक्ति	मृत्युदंड की सजा/कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को माफ कर सकता है	मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता; सैन्य मामलों में कोई भूमिका नहीं
संवैधानिक विवेकाधिकार	कोई संवैधानिक विवेकाधिकार नहीं	किसी विधेयक को सुरक्षित रखने, राष्ट्रपति शासन लगाने और किसी निकटवर्ती केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासन के संदर्भ में संवैधानिक विवेकाधिकार
महाभियोग की स्थिति	संविधान का उल्लंघन	कोई आधार निर्धारित नहीं

आगे की राह:

- **संघीय व्यवस्था को मज़बूत करना:** राज्यपाल के कार्यालय के दुरुपयोग को रोकने के लिये भारत में **संघीय व्यवस्था को मज़बूत करने** की आवश्यकता है।
 - इस संबंध में, **अंतरराज्यीय परिषद और संघवाद** के सदन के रूप में **राज्य सभा** की भूमिका को मज़बूत किया जाना चाहिये।
- **राज्यपाल की नियुक्ति की पद्धति में सुधार:** राज्यपाल की **नियुक्ति राज्य विधानमंडल** द्वारा निर्मित पैनल के द्वारा की जानी चाहिये तथा वास्तविक रूप से नियुक्ति प्राधिकारी अंतर-राज्य परिषद से होना चाहिये, न कि केन्द्र सरकार का।
- **राज्यपाल की आचार संहिता:** इस "आचार संहिता" में कुछ "मानदंड और सदिधांत" स्थापित किये जाने चाहिये, जो राज्यपाल के "वविक" और उसकी शक्तियों के उपयोग को निर्दिशति करें, जिसका उपयोग वह अपने निर्णय के आधार पर कर सकता है।
- **वविकाधीन शक्तियों के प्रयोग को प्रतर्बिधति करना:** राज्यपालों द्वारा 'वविकाधीन शक्तियों' का प्रयोग 'स्वस्थ एवं लोकतांत्रिक परंपराओं द्वारा निर्दिशति' होना चाहिये।
 - उन्हें किसी भी राजनीतिक ववचारधारा से जुड़ने से बचना चाहिये तथा संवैधानिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करने के लिये नष्पिक्षता के गुण को बनाए रखना चाहिये।

दृष्टमैन्स प्रश्न

प्रश्न: राज्यपाल से संबंधित चर्चाओं पर चर्चा कीजिये और आवश्यकता सुधारों पर भी चर्चा कीजिये?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

??????????:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर ववचार कीजिये: (2018)

1. किसी राज्य के राज्यपाल के वरुद्ध उसकी पदावधिके दौरान किसी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्यावाही संस्थापित नहीं की जाएगी।
2. किसी राज्य के राज्यपाल की परलिबधियां और भत्ते उसकी पदावधिके दौरान कम नहीं किये जाएँगे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (C)

प्रश्न. प्नमिनलखिति में से कौन-सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई वविकाधीन शक्तियाँ हैं? (2014)

1. भारत के राष्ट्रपतको राष्ट्रपतशासन अधरिपति करने के लिये रपिर्ट भेजना।
2. मंत्रियों की नियुक्ति करना।
3. राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतपिय वधियकों को भारत के राष्ट्रपतके ववचार के लिये आरक्षति करना।
4. राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिये नियम बनाना।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

प्रश्न. नमिन्लखिति कथनों में से कौन-सा एक सही है? (2013)

- (a) भारत में एक ही व्यक्तिको एक ही समय में दो या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता ।
(b) भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त किये जाते हैं ।
(c) भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है ।
(d) वधियायी व्यवस्था वाले संघ राज्यक्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्तिउपराज्यपाल द्वारा, बहुमत समर्थन के आधार पर, की जाती है ।

उत्तर: (c)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/office-of-governor-and-related-concerns>

